



## इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव

### प्रलिस के लयः

संयुक्त राष्ट्र मानवाधकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR), #KEEPITON गठबंधन, वशिव बैंक ।

### मेन्स के लयः

इंटरनेट शटडाउन और उसके नहऱऱरथ ।

## चरचा में क्यौं?

हाल ही में, [संयुक्त राष्ट्र मानवाधकार उच्चायुक्त कार्यालय \(OHCHR\)](#) द्वारा इंटरनेट शटडाउन नामक एक रपौरट प्रकाशतऱ की गईः जसऱमें इसके रुझान, कारण, कानूनी नहऱऱरथ और मानवाधकारों पर प्रभाव, वर्णतऱ हैं तथा कहा गया है कऱ इंटरनेट बंद करने से लोगों की सुरक्षा और कल्याण प्रभावतऱ होता है, सूचना प्रवाह में बाधा आतऱ है और अर्थव्यवस्था को क्षतऱ पहुँचतऱ है ।

## इंटरनेट शटडाउनः

### ■ परचयः

- इंटरनेट शटडाउन के उपाय का उपयोग आमतौर पर तब कयऱा जाता है जब नागरकऱ अशांतऱ की स्थतऱऱ होती है, ताकऱ सरकारी कार्रवाइयों के संबंघ में सूचनाओं के प्रवाह को अवरुद्ध कयऱा जा सके ।
- शटडाउन में अक्सर इंटरनेट कनेक्टवऱतऱ या प्रभावतऱ सेवाओं की पहुँच को पूर्णतः प्रतऱबंधतऱ कयऱा जाता है । हालाँकऱ सरकारें तेज़ी से बैडवडऱथ को कम करने या मोबाइल सेवा को 2G तक सीमतऱ करने का सहारा लेतऱ हैं, जो नाममात्र की पहुँच बनाए रखते हुए इंटरनेट का सारथक उपयोग करना बेहद मुश्कलऱ बना देतऱ है ।
- दुनयऱा भर की सरकारों ने कई कारणों का हवाला देते हुए इंटरनेट को बंद करने का सहारा लयऱा है
- इसके अलावा वीडयो, लाइव प्रसारण और अन्य पत्रकारतऱ कार्रयों को साझा करना तथा देखना मुश्कलऱ हो जाता है, जनऱहें अक्सर नागरकऱ समाज आंदोलनों, सुरक्षा उपायों के साथ-साथ चुनावी कार्रवाही के दौरान आदेश दयऱा जाता है और मानवाधकारों की नगरऱानी व रपौरटगऱ को गंभीर रूप से प्रतऱबंधतऱ करता है ।

### ■ संबंघतऱ अंतरराष्टरीय ढाँचेः

- इंटरनेट शटडाउन कई मानवाधकारों को गंभीर रूप से प्रभावतऱ करता है, साथ ही यह अभवऱयकतऱ की स्वतंत्रता और सुरक्षा तथा लोकतांत्रकऱ समाजों की नीव में से एक व्यकतऱ के पूर्ण वकऱस के लयऱे अनवऱर्य शरत की जानकारी तक पहुँच को त्वरतऱ रूप से प्रभावतऱ करता है ।
- यह नागरकऱ और राजनीतकऱ अधकारों और अन्य मानवाधकार उपकरणों (अर्थात् [मानवाधकारों की सार्वभौमकऱ घोषणा](#)) पर अंतरराष्टरीय अनुबंध में गारंटीकृत अन्य सभी अधकारों के लयऱे एक मानदंड है ।
- [सतत वकऱस लक्ष्य](#) अन्यायपूर्ण प्रतऱबंधों से मुक्त, सार्वभौमकऱ रूप से उपलब्ध और सुलभ इंटरनेट द्वारा कार्रय करने के लयऱे राज्यों के मानवाधकार दायतऱवों को सुदृढ करते हैं ।
- संचार नेटवर्क में अंतरराष्टरीय कनेक्टवऱतऱ की सुवधा के लयऱे स्थापतऱ, [अंतरराष्टरीय दूरसंचार संघ](#) (ITU) मानकों को अपनाने पर कार्रय करता है जो सुनश्चऱतऱ करता है कऱ नेटवर्क और प्रौद्योगकऱयऱों आपस में जुडतऱ हैं तथा इंटरनेट तक पहुँच में सुधार करने का प्रयास करतऱ हैं ।

## प्रमुख नषऱकरषः

### ■ वैश्वकऱ परदऱशयः

- दुनयऱा का धयऱान खींचने वाला पहला बड़ा इंटरनेट शटडाउन वर्ष 2011 में मसऱर में हुआ था और इसके साथ ही सैकड़ों गरऱफ्तारयऱों और हतऱयाएँ भी हुई थीं ।
- #कीपइऑन गठबंधन ([#KeepItOn coalition](#)), जो दुनयऱा भर में इंटरनेट शटडाउन एपसऱड की नगरऱानी करता है, द्वारा वर्ष

2016-2021 तक 74 देशों में 931 शटडाउन का दस्तावेजीकरण किया गया।

- उस अवधि के दौरान 12 देशों द्वारा 10 से अधिक शटडाउन लागू किये गए। वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में कई शटडाउन का सामना किया गया है, लेकिन अधिकांश रपिर्ट एशिया और अफ्रीका में हुई है।
- नागरिक समाज समूहों द्वारा दर्ज किये गए शटडाउन में से 132 को आधिकारिक तौर पर अभद्र भाषा, दुष्प्रचार या अवैध या हानिकारक समझी जाने वाली सामग्री के अन्य रूपों के प्रसार को नयितरति करने की आवश्यकता द्वारा उचित ठहराया गया था।

#### ■ भारतीय परिदृश्य:

- भारत ने इंटरनेट कनेक्शन को 106 बार अवरुद्ध या बाधित किया तथा भारत के कम-से-कम 85 इंटरनेट शटडाउन एपिसोड जम्मू और कश्मीर में हुए।
- नागरिक समाज समूहों द्वारा वर्ष 2016-2021 तक दर्ज किये गए सभी शटडाउन में से लगभग आधे को वरिध और राजनीतिक संकटों के संदर्भ में किया गया था, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक शकियतों की एक वरिध शृंखला से संबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान 225 शटडाउन दर्ज किये गए थे।

#### ■ चुनाव के दौरान शटडाउन:

- यह डिजिटल उपकरणों तक पहुँच को समाप्त करता है जो चुनाव प्रचार, सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देने, मतदान करने और चुनावी प्रक्रियाओं की देख-रेख के लिये महत्वपूर्ण हैं।
- अकेले वर्ष 2019 में 14 अफ्रीकी देशों ने चुनावी अवधि के दौरान इंटरनेट तक पहुँच को बाधित कर दिया।
- ये व्यवधान नषिकष पत्रकारों और मीडिया के काम को सामान्य रूप से बाधित करते हैं। युगांडा में शटडाउन ने हसिक दमनकारी उपायों की रपिर्टों के बीच वर्ष 2021 में चुनावों के मीडिया कवरेज को कमजोर कर दिया।
- चुनावी अवधि के दौरान वरिध के बाद शटडाउन बेलारूस और नाइजर जैसे देशों में भी रपिर्ट किये गए थे।

#### ■ इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव:

- **आर्थिक गतिविधियों पर:** यह सभी क्षेत्रों के लिये बड़ी आर्थिक लागत का कारण बनता है, वरिध लेनदेन, वाणज्य और उद्योग को बाधित करता है।
  - **वशिव बैंक** ने हाल ही में गणना की है कि अकेले म्यांमार में इंटरनेट शटडाउन की लागत फरवरी-दसंबर 2021 से लगभग 2.8 बलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो पछिले दशक में हुई आर्थिक प्रगत को उलट देती है।
- **शकषा पर:** यह सीखने के परणामों को कमजोर करता है और शकषकों, स्कूल प्रशासकों, परवारों के बीच शकषा योजना एवं संचार में हस्तक्षेप करता है।
- **स्वास्थ्य और मानवीय सहायता तक पहुँच पर:**
  - अध्ययनों ने स्वास्थ्य प्रणालियों पर शटडाउन के महत्वपूर्ण प्रभावों को दिखाया है, जिसमें तत्काल चकितिसा देखभाल जुटाना, आवश्यक दवाओं की डलिवरी और उपकरणों के रखरखाव में बाधा डालना, चकितिसा कर्मियों के बीच स्वास्थ्य सूचनाओं के आदान-प्रदान को सीमित करना और आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य सहायता को बाधित करना शामिल है।
  - सहायता प्रदान करने के लिये मानवीय अभकिरत्ताओं की कषमता पर इंटरनेट शटडाउन का गहरा प्रभाव पड़ता है। आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं के वरिध के लिये महत्वपूर्ण सूचना के प्रवाह को बाधित किया जा सकता है।
    - म्यांमार में इंटरनेट शटडाउन ने कथित तौर पर स्थानीय सहायता संगठनों को संकट में डाल दिया, क्योंकि इसने उन्हें धन मांगने और प्राप्त करने से रोका था।

## इंटरनेट शटडाउन हेतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दशान-नरिदेश:

- जैसा कि अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया कि इंटरनेट शटडाउन भारतीय संवधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करता है। यह एक उचित प्रतबिध के रूप में कार्य करता है और इसे केवल तभी अधनियमति किया जाना चाहिये जब सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये कोई वास्तविक खतरा हो। कुछ संतुलन परीक्षण किये जाने चाहिये तथा केवल अत्यधिक आवश्यक होने पर ही सरकार को इस अत्यंत प्रतबिधात्मक कदम का प्रयोग करना चाहिये।

## आगे की राह

- रपिर्ट में कहा गया है कि इंटरनेट शटडाउन की अधिक आवृत्ति की प्रवृत्ति को रोकने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक उपायों और उनके प्रभावों की सीमित दृश्यता है।
- रपिर्ट में राज्यों से शटडाउन से परहेज करने, इंटरनेट पहुँच को अधिकतम करने और संचार के रास्ते में कई बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया गया है।
- इसने कंपनियों से व्यवधानों पर सूचनाओं को तेजी से साझा करने और यह सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया कि वे शटडाउन को रोकने के लिये सभी संभव कानूनी उपाय करें जिन्हें उन्हें लागू करने के लिये कहा गया है।
- शटडाउन डिजिटल डिविड को कम करने के प्रयासों, त्वरित आर्थिक और सामाजिक विकास के वादे को कमजोर करते हैं, जिससे सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि को खतरा होगा।

## स्रोत: डाउन टू अर्थ

